



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2007/आषाढ़ 5, 1929

No. 129]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2007/ASADHA 5, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(एनवाईकेएस की ओर से, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य कार्यालय, तमिलनाडु, चेन्नई)

अधिसूचना

चेन्नई, 22 जून, 2007

फा. सं. 806/एसपी/एनवाईकेएस राज्य कार्यालय.—रिकार्ड के लिए यह उल्लेख किया जाता है कि राज्य युवा संघ बोर्ड के लिए राज्य योजना समिति, जो स्वायत्त दर्जे का निकाय है जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित है, के अध्यक्ष को भारत सरकार के सचिव के समान प्रोटोकॉल दर्जा दिया गया है।

वह भारत सरकार के नियमों के अनुसार अपने अवकाश ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा।

जरूरी होने पर अध्यक्ष, प्रतिनियुक्ति पर सरकार की अन्य जिम्मेदारियाँ भी ले सकता है।

अध्यक्ष राज्य युवा संघ बोर्ड के निदेशक मंडल को नामांकित करेगा, जिसमें अधिकतम पाँच सदस्य होंगे, जिसमें दो अवकाश-प्राप्त सरकारी कर्मचारी होंगे जो अपनी सेवाओं के लिए मानदेय के पात्र होंगे, और तीन सेवारत सरकारी कर्मचारियों में से होंगे। वह कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्रभारी भी होगा।

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, तमिलनाडु अध्याय द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार।

1. सबसे पहले योजना समिति के अध्यक्ष की सलाह से 7 सदस्य चुने जाने चाहिए।
2. युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित।
3. तमिलनाडु में स्त्री और पुरुष दोनों के सभी स्वयं सहायता समूहों की नेटवर्किंग द्वारा स्वयं सहायता समूहों का संघ बनाया जाना चाहिए।
4. हर जिले में 5 सदस्यों की सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिए।
5. एसवाईएफबी (SYFB) को नाबार्ड (NABARD) समर्थन और सहयोग देगा।
6. नाबार्ड के साथ राज्य योजना समिति एसवाईएफबी को नियमित समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग देगी।
7. निधि की किसी जरूरत की स्थिति में, नाबार्ड को उसके विचारार्थ और सहायता के लिए, अलग वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
8. राज्य योजना समिति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही, एसवाईएफबी को अपनी गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी।
9. राज्य योजना समिति का अध्यक्ष पद पर रहेगा और उसका प्रोटोकॉल दर्जा भारत सरकार के सचिव के समान होगा।
10. नाबार्ड एसवाईएफबी का संस्थापक-सदस्य बना रहेगा और इसकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करेगा।
11. महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ तमिलनाडु में नेहरू युवा केंद्रों के सभी युवा क्लबों की नेटवर्किंग करके तीन महीनों में राज्य युवा संघ बनाया जाना चाहिए।

12. वित्तीय सहायता वित्तपोषण एजेंसियों, सरकारी विभागों या कॉर्पोरेट घरानों से ली जा सकती है।

महिला स्वयं सहायता समूहों और एनवाईके (NYK) युवाओं का संघ सहकारी अधिनियम का अनुपालन करके अपना अध्यक्ष चुनेगा। राज्य योजना समिति राज्य युवा संघ बोर्ड का नियामक निकाय है और इसलिए एसवाईएफबी का अध्यक्ष राज्य योजना समिति के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में काम करेगा।

राज्य योजना समिति सामाजिक और आर्थिक परियोजना गतिविधियाँ आयोजित करती है।

एसवाईएफबी को अपने संचालन और गतिविधियों के लिए दान, अनुदान सहायता, और व्यक्तियों, वित्तीय संस्थान और कॉर्पोरेट घरानों से योगदान प्राप्त करने का अधिकार है।

एसपीसी के अध्यक्ष को एसवाईएफबी के सदस्य को प्रति व्यक्ति रुपए 2,00,000 तक का ऋण स्वीकृत करने का अधिकार है।

एनवाईकेएस राज्य कार्यालय, तमिलनाडु की ओर से,

आर. राजंगम, अतिरिक्त कानूनी सलाहकार

[विज्ञापन-III/4/असा./92-एन/07]

संदर्भ :

- क. केंद्रीय मंत्री/DYC बैठक/सेटअप/राज्य युवा संघ बोर्ड/चेन्नई 15-04-2007
- ख. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/MCID/194 CGM/2007
- ग. स्वीकृत पत्र 14-06-2007 मंडलीय निदेशक/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम/केंद्रीय रजिस्ट्रार नई दिल्ली।
- घ. अतिरिक्त केंद्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार, तिथि 16-5-2007
- ड. विभाग प्रमुख द्वारा अधिसूचना सं. : 3A/116-2007 (910/07 ADV/CHN) न्यायिक अधिसूचना सरकार गजट (तमिलनाडु राज्य)।
- च. 22-6-2007 NYKS/मंडलीय निदेशक/अधिसूचना-REG/

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(On behalf of the NYKS, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, State Office, Tamil Nadu, Chennai)

NOTIFICATION

Chennai, the 22nd June, 2007

F. No. 806/SP/NYKS State Office.—This is to State for record that the Chairman of the State Planning Committee for State Youth Federation Board, an autonomous status body consisting of 7 members including the chairman supported by the Ministry of Youth Affairs and Sports has been endowed with the protocol status on par with the Secretaries of Government of India.

He shall hold office until his retirement as per the norms of Government of India.

The Chairman can, if need be, hold other Government responsibilities on deputation.

The Chairman will nominate the Board of directors of State Youth Federation Board, to the maximum member of five, comprising two retired Government officials who will be entitled to honorarium for their services, and three members from among Government officials in services. He will also be in charge of appointing the office staff.

as per suggestions given by Ministry of Law and Justice Government of India, Tamil Nadu chapter.

1. First of all seven members should be selected in consultation with the Chairman, Planning Committee.
2. Supported by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India.
3. A federation of Self Help Groups shall be formed by networking all the Self Help Groups of both the sexes in Tamil Nadu.
4. An advisory committee comprising 5 members should be formed in each district.
5. NABARD will give support and co-operation to SYFB.
6. State Planning Committee will give regular support, guidance and cooperation to SYFB along with NABARD.
7. In the event of any need for funds, a separate financial report should be submitted to NABARD for its consideration and assistance.
8. Only after obtaining the consent of State Planning Committee, SYFB will be allowed to carry out its activities.
9. The Chairman of State Planning Committee will hold office and his protocol status will be on par with the Secretaries of Government of India.

10. NABARD will remain the Founder-Member of SYFB and guide its activities.
11. The State Youth Federation should be formed within three months networking all the youth clubs of Nehru Yuva Kendra in Tamil Nadu along with the women Self Help Groups.
12. Financial support can be availed from Funding Agencies, Government Departments or Corporate Houses.

The Federation of Self Help Groups of Women and NYK youth will elect their chairperson following the norms of cooperative Act.

State Planning Committee is the regulatory body of the State Youth Federation Board and hence the Chairman of SYFB with function under the supervision of the Chairman of State Planning Committee.

State Planning committee organised social and economic project activities.

SYFB is empowered to raise the required funds for its functioning and activities through donation, grants in aid, and contribution from individuals, financial institution and corporate houses.

The Chairman of SPC has the power of sanctions loans upto Rs. 2,00,000 per person is the member of SYFB.

On the behalf of NYKS,
State Office, Tamil Nadu.

R. RAJANGAM, Addl. Legal Adviser

[Advt. III/4/Exty/92-N/07]

- Ref. :
- A. Union Minister/DYC Meeting/Setup/State Youth Federation Board/Chennai 15-04-2007.
 - B. National Bank for Agricultural and Rural Development/MCID/194 CGM/2007.
 - C. Acceptance Letter 14-6-2007 Zonal Director/Multi State Co-operative Society Act/Central Registrar New Delhi.
 - D. Additional Central Government, Standing Counsel dated 16-5-2007.
 - E. Notification by Head of the Department No. 3A/116-2007 (910/07/ADV/CHN) Judicial Notification Government Gazette (State of Tamil Nadu).
 - F. 22-6-2007 NYKS/Zonal Director/Notification-REG/